भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2568
उत्तर देने की तारीख-17/03/2025

एनएएसी के अंतर्गत महत्वपूर्ण सुधार

†2568.श्री वी.के. श्रीकंदन:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) ने लगभग 900 से अधिक सहकर्मी मूल्यांकनकर्ताओं को मूल्यांकन कार्य से हटा दिया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या यह भी सच है कि राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद ने पिछले वर्ष तीन दौर की भर्ती में समानांतर रूप से 1,000 नए मूल्यांकनकर्ताओं को भी शामिल किया है;
(घ) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद ने अपनी प्रत्यायन प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा एवं पारदर्शिता बढ़ाने के लिए पर्याप्त सुधार किए हैं; और
(ङ.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ग): जैसा कि राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) द्वारा सूचित किया गया है, पिछले डेढ़ वर्षों में, एनएएसी ने फीडबैक, कार्यकारी प्रोटोकॉल में भिन्नता, एनएएसी मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा गलत जानकारी प्रदान करने जैसे विभिन्न पहलुओं पर ध्यान दिया है और 840 मूल्यांकनकर्ताओं को हटा दिया है। इसके अलावा, मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद नए मूल्यांकनकर्ताओं को शामिल करके मूल्यांकनकर्ताओं के अपने डेटाबेस को लगातार अद्यतित करता रहता है जो प्रख्यात शिक्षाविद/शिक्षा प्रशासक होते हैं। एनएएसी ने वर्ष 2023-24 और वर्ष 2024-25 में 1461 मूल्यांकनकर्ताओं को जोड़ा है।

(घ) और (ङ): उच्चतर शिक्षण संस्थानों (एचईआई) के मूल्यांकन और प्रत्यायन को मजबूत करने के लिए, भारत सरकार ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कानपुर के संचालक मंडल के अध्यक्ष और आईआईटी परिषद की स्थायी समिति के अध्यक्ष डॉ के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। इस समिति ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के दृष्टिकोण के अनुरूप रणनीतिक सुधारों की शुरूआत और प्रौद्योगिकी-संचालित

प्रणालियों के माध्यम से उच्चतर शिक्षण संस्थानों के अनुमोदन, मान्यता और रैंकिंग के लिए एक सरल, विश्वास-आधारित, उद्देश्यपूर्ण और तर्कसंगत प्रणाली अपनाने की आवश्यकता पर विचार किया है। इस समिति द्वारा की गई सिफारिशों को मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया है।

राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद की कार्यकारी समिति ने डॉ. राधाकृष्णन समिति की रिपोर्ट की सिफारिशों को अपना लिया है।

*****